

**Title:** Demand to include the Santhali and major spoken language in state of Jharkhand in the Eight Schedule of the Constitution.

**श्री सालखन मुर्मू (मयूरभंज) :** महोदय, मैं भारत के आदिवासियों से संबंधित एक गम्भीर मामला सदन के समक्ष और सरकार के समक्ष रखना चाहता हूँ। संविधान की आठवीं अनुसूची में आज तक भी एक आदिवासी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। जबकि संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 29(1) में यह बात लिखी गई है कि जिन लोगों की अपनी भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उनको बचाने और बढ़ाने का अधिकार है। इस विषय को मैंने दो बार 12वीं लोकसभा में उठाया और इस बार भी उठाया है। इस विषय में माननीय गृहमंत्री जी ने लिखित रूप में कहा है कि हम एक हाई-पावर कमेटी बनाकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। इसके विरोध में बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा और झारखण्ड राज्यों के लोग आल-इंडिया संथाली भाषा मोर्चा के नेतृत्व में आन्दोलन करने के लिए मजबूर हैं। 25 सितम्बर को हमने रेल-रोको अभियान किया और फिर 8 दिसम्बर को रेल-रोको अभियान करने के लिए मजबूर हैं। हम मांग करते हैं कि संथाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए और झारखण्ड प्रदेश की कम से कम एक आदिवासी भाषा, जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, संथाली को राजभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए।